INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF MANAGEMENT SOCIOLOGY & HUMANITIES



ISSN 2277 – 9809 (online)
ISSN 2348 - 9359 (Print)

An Internationally Indexed Peer Reviewed & Refereed Journal

www.IRJMSH.com
www.isarasolutions.com

Published by iSaRa Solutions

भारत-भूटान संबंधों में बदलते राजनीतिक एवं सामरिक समीकरणों का आलोचनात्मक अध्ययन: समकालीन दक्षिण एशियाई राजनीति के संदर्भ में

डॉ. बृजेश स्वरुप सोनकर

असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग

कर्म क्षेत्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय, इटावा (उ.प्र.)

सारांश

प्रस्तुत शोध-पत्र में भारत और भूटान के द्विपक्षीय संबंधों में विकसित होते राजनीतिक, आर्थिक एवं सामरिक समीकरणों का समकालीन दक्षिण एशियाई राजनीति के संदर्भ में आलोचनात्मक विश्लेषण किया गया है। अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य यह समझना रहा कि ऐतिहासिक विश्वास, भौगोलिक निकटता, सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं तथा आर्थिक सहयोग ने दोनों देशों के संबंधों को किस प्रकार प्रभावित किया है। वर्ष 1949 की मैत्री संधि, वर्ष 2007 में उसके संशोधित स्वरूप, जलविद्युत सहयोग, सीमा सुरक्षा, चीन के साथ भूटान के सीमा-विवाद तथा भारत-चीन प्रतिस्पर्धा ने द्विपक्षीय संबंधों को विशिष्ट रणनीतिक महत्त्व प्रदान किया है। अध्ययन में यह भी पाया गया कि भारत-भूटान संबंध केवल परंपरागत सुरक्षा साझेदारी तक सीमित नहीं हैं, बल्कि व्यापार, संपर्क, शिक्षा, डिजिटल विकास एवं ऊर्जा संक्रमण जैसे क्षेत्रों में भी उनका विस्तार हुआ है। तथापि, भूटान की विदेश नीति में विविधीकरण की आकांक्षा, चीन के साथ सीमा-वार्ता और आर्थिक निर्भरता से जुड़े प्रश्न नई चुनौतियाँ प्रस्तुत करते हैं। निष्कर्षतः, द्विपक्षीय संबंधों की दीर्घकालिक स्थिरता पारस्परिक सम्मान, भूटान की संप्रभुता के प्रति संवेदनशीलता तथा समान हितों पर आधारित सहयोग को सुदृढ़ करने पर निर्भर करती है।

मुख्य शब्द: भारत-भूटान संबंध, दक्षिण एशियाई राजनीति, सामरिक सहयोग, जलविद्युत, चीन-भूटान सीमा-विवाद, क्षेत्रीय सुरक्षा, विदेश नीति।

प्रस्तावना

दक्षिण एशिया की समकालीन राजनीति में भारत और भूटान के संबंध ऐतिहासिक विश्वास, भौगोलिक निकटता, पारस्परिक सहयोग तथा साझा सुरक्षा हितों पर आधारित एक विशिष्ट द्विपक्षीय साझेदारी के रूप में विकसित हुए हैं। हिमालयी क्षेत्र में स्थित भूटान भौगोलिक दृष्टि से एक छोटा देश होने के बावजूद दक्षिण एशिया की भू-राजनीति में महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। भारत और चीन के बीच इसकी अवस्थिति, भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र से इसकी निकटता तथा चीन के साथ इसकी अनिर्धारित अंतरराष्ट्रीय सीमा इसे सामरिक दृष्टि से संवेदनशील बनाती है। इस कारण भारत-भूटान संबंधों का महत्त्व केवल दो पड़ोसी देशों के पारस्परिक संबंधों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हिमालयी क्षेत्र में शांति, क्षेत्रीय स्थिरता और शक्ति-संतुलन की व्यापक प्रक्रिया से भी जुड़ा हुआ है। भारत और भूटान के संबंधों का ऐतिहासिक विकास आपसी विश्वास तथा संस्थागत सहयोग की क्रमिक प्रक्रिया को प्रतिबिंबित करता है। वर्ष 1949 में संपन्न मैत्री संधि ने दोनों देशों के बीच औपचारिक संबंधों को आधार प्रदान किया। इसके पश्चात्

राजनीतिक संवाद, विकास सहायता, व्यापार तथा सुरक्षा सहयोग के विभिन्न माध्यमों से द्विपक्षीय संबंधों का विस्तार हुआ। वर्ष 1968 में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध स्थापित होने से इस सहयोग को अधिक व्यवस्थित स्वरूप प्राप्त हुआ। वर्ष 2007 में मैत्री संधि का संशोधन द्विपक्षीय संबंधों के विकास में एक महत्त्वपूर्ण पड़ाव सिद्ध हुआ। संशोधित संधि ने दोनों देशों की स्वतंत्रता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति सम्मान को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया। इससे भारत-भूटान संबंधों को परंपरागत सुरक्षा सहयोग से आगे बढ़ाकर पारस्परिक सम्मान, स्वतंत्र निर्णय क्षमता तथा साझा विकास संबंधी प्राथमिकताओं के आधार पर समझने का अवसर मिला।

भारत-भूटान संबंधों की एक प्रमुख विशेषता यह है कि दोनों देशों ने समय के साथ अपने सहयोग के क्षेत्रों का निरंतर विस्तार किया है। भारत भूटान का प्रमुख व्यापारिक साझेदार तथा विकास सहयोग का महत्त्वपूर्ण स्रोत रहा है। सड़क, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, डिजिटल प्रौद्योगिकी और संस्थागत क्षमता निर्माण जैसे क्षेत्रों में भारत के सहयोग ने भूटान की विकास प्रक्रिया को समर्थन प्रदान किया है। दूसरी ओर, भूटान की जलविद्युत क्षमता भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं, विशेषकर स्वच्छ ऊर्जा के विस्तार, के संदर्भ में महत्त्वपूर्ण है। जलविद्युत परियोजनाओं के माध्यम से भूटान को राजस्व प्राप्त होता है, जबकि भारत को विद्युत आपूर्ति तथा क्षेत्रीय ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देने का अवसर मिलता है। इस प्रकार आर्थिक एवं ऊर्जा सहयोग ने दोनों देशों के संबंधों को राजनीतिक विश्वास के साथ-साथ व्यावहारिक पारस्परिक हितों का आधार भी प्रदान किया है।

तथापि, भारत-भूटान संबंधों की प्रकृति को केवल ऐतिहासिक मित्रता और सहयोग की उपलब्धियों के आधार पर पूरी तरह नहीं समझा जा सकता। समकालीन दक्षिण एशियाई राजनीति में बदलते शक्ति-समीकरण, चीन की बढ़ती क्षेत्रीय सक्रियता तथा भारत-चीन प्रतिस्पर्धा ने भूटान की भौगोलिक स्थिति को और अधिक महत्त्वपूर्ण बना दिया है। चीन और भूटान के बीच सीमा विवाद लंबे समय से दोनों देशों के संबंधों का एक संवेदनशील विषय रहा है। वर्ष 2017 का डोकलाम गतिरोध इस तथ्य को स्पष्ट करता है कि भूटान से संबंधित सीमा प्रश्न व्यापक क्षेत्रीय सुरक्षा और सामरिक शक्ति-संतुलन को प्रभावित कर सकते हैं। भारत के लिए इन परिस्थितियों में भूटान के साथ सुरक्षा समन्वय बनाए रखना महत्त्वपूर्ण है, जबकि भूटान के लिए अपनी क्षेत्रीय अखंडता, स्वतंत्र विदेश नीति तथा राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। यही स्थिति भारत-भूटान संबंधों को समकालीन भू-राजनीतिक विश्लेषण का एक महत्त्वपूर्ण विषय बनाती है। इसके अतिरिक्त, भूटान की आर्थिक विकास संबंधी आवश्यकताएँ और अपनी विदेश नीति में विकल्पों के विस्तार की आकांक्षा भी द्विपक्षीय संबंधों के बदलते स्वरूप को प्रभावित करती हैं। भारत के साथ गहरे व्यापारिक एवं आर्थिक संबंध भूटान को बड़े बाजार, निवेश और तकनीकी सहयोग तक पहुँच प्रदान करते हैं, किंतु किसी एक प्रमुख व्यापारिक साझेदार पर अत्यधिक निर्भरता आर्थिक विविधीकरण की आवश्यकता भी उत्पन्न करती है। इसी प्रकार जलविद्युत परियोजनाओं ने दोनों देशों को महत्त्वपूर्ण लाभ पहुँचाए हैं, लेकिन परियोजनाओं की लागत, निर्माण में विलंब, वित्तीय जोखिम तथा पर्यावरणीय प्रभाव जैसे प्रश्न इनके दीर्घकालिक लाभों के मूल्यांकन को आवश्यक बनाते हैं। अतः द्विपक्षीय संबंधों की सफलता का आकलन केवल सहयोग के क्षेत्रों की संख्या अथवा आर्थिक लेन-देन की मात्रा से नहीं, बल्कि इस आधार पर भी किया जाना चाहिए कि सहयोग दोनों देशों की विकास आवश्यकताओं, आर्थिक स्थिरता और दीर्घकालिक हितों को किस सीमा तक पूरा करता है।

राजनीतिक दृष्टि से भारत-भूटान संबंध छोटे राज्य की रणनीतिक स्वायत्तता और क्षेत्रीय शक्ति के प्रभाव के बीच संतुलन को समझने का भी अवसर प्रदान करते हैं। भूटान की विदेश नीति को केवल भारत और चीन के बीच प्रतिस्पर्धा की प्रतिक्रिया के रूप में देखना उसकी स्वतंत्र राजनीतिक भूमिका को सीमित कर सकता है। भूटान अपने राष्ट्रीय हितों, सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं, आर्थिक विकास तथा अंतरराष्ट्रीय संपर्क के विस्तार को ध्यान में रखकर निर्णय लेता है। इसलिए भारत के लिए दीर्घकालिक साझेदारी को सुदृढ़ बनाए रखने हेतु भूटान की संप्रभुता, स्वतंत्र निर्णय क्षमता और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं का सम्मान करना आवश्यक है। इसी प्रकार भूटान के लिए भारत के साथ स्थिर एवं विश्वासपूर्ण संबंध बनाए रखना उसकी सुरक्षा और आर्थिक प्रगति के महत्त्वपूर्ण आधारों में से एक है। इस परिप्रेक्ष्य में द्विपक्षीय संबंधों को एकपक्षीय निर्भरता के बजाय पारस्परिक हितों, सहयोग और संतुलित साझेदारी की दृष्टि से समझना अधिक उपयुक्त है। समकालीन परिस्थितियों में भारत-भूटान संबंधों का विस्तार पारंपरिक सुरक्षा और जलविद्युत सहयोग से आगे बढ़कर संपर्क अवसंरचना, रेल एवं सड़क परिवहन, डिजिटल विकास, पर्यटन, कौशल निर्माण और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों तक हो रहा है। इन नए क्षेत्रों में सहयोग दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को अधिक विविधतापूर्ण बनाने तथा पारस्परिक निर्भरता को व्यापक विकास साझेदारी में रूपांतरित करने की क्षमता रखता है। इसके साथ ही, क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा, सीमा संबंधी अनिश्चितताओं और आर्थिक चुनौतियों के कारण दोनों देशों के लिए कूटनीतिक संवाद तथा संस्थागत समन्वय को निरंतर मजबूत बनाए रखना भी आवश्यक है। इस प्रकार भारत-भूटान संबंध एक ओर ऐतिहासिक निरंतरता और राजनीतिक विश्वास का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, तो दूसरी ओर बदलती क्षेत्रीय परिस्थितियों के अनुरूप अपनी प्राथमिकताओं और सहयोग के स्वरूप को पुनर्संतुलित करने की चुनौती का भी सामना करते हैं।

इन्हीं तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत शोध-पत्र में भारत-भूटान संबंधों के ऐतिहासिक विकास, राजनीतिक एवं कूटनीतिक सहयोग, सामरिक हितों, चीन-भूटान सीमा विवाद, आर्थिक परस्पर निर्भरता तथा ऊर्जा साझेदारी का विश्लेषण किया गया है। अध्ययन में यह समझने का प्रयास किया गया है कि बदलते क्षेत्रीय शक्ति-संतुलन ने दोनों देशों के संबंधों को किस प्रकार प्रभावित किया है तथा पारंपरिक मैत्री को बनाए रखते हुए उभरती चुनौतियों का सामना करने की क्या संभावनाएँ हैं। साथ ही, द्विपक्षीय सहयोग की उपलब्धियों के साथ उसकी सीमाओं, आर्थिक असमानताओं और भूटान की रणनीतिक स्वायत्तता से जुड़े प्रश्नों का आलोचनात्मक परीक्षण भी किया गया है। इस प्रकार प्रस्तुत अध्ययन का मूल उद्देश्य भारत-भूटान संबंधों को केवल मैत्रीपूर्ण पड़ोसी संबंधों के रूप में नहीं, बल्कि समकालीन दक्षिण एशियाई राजनीति में सुरक्षा, संप्रभुता, आर्थिक सहयोग और क्षेत्रीय शक्ति-संतुलन के परस्पर संबंधों को स्पष्ट करने वाले एक महत्त्वपूर्ण राजनीतिक अध्ययन के रूप में स्थापित करना है।

शोध समस्या एवं अध्ययन का महत्त्व

भारत और भूटान के बीच व्यापक राजनीतिक विश्वास तथा सुरक्षा सहयोग विद्यमान है, फिर भी बदलते क्षेत्रीय शक्ति-संतुलन ने इस साझेदारी के सामने नए प्रश्न उपस्थित किए हैं। प्रमुख शोध समस्या यह है कि भारत-भूटान संबंधों में पारंपरिक रणनीतिक निकटता को बनाए रखते हुए भूटान की स्वतंत्र विदेश नीति, आर्थिक विविधीकरण तथा चीन के साथ सीमा-संबंधी वार्ताओं से उत्पन्न परिस्थितियों का किस प्रकार संतुलन किया जा सकता है।

इस अध्ययन का महत्त्व इस तथ्य में निहित है कि यह द्विपक्षीय संबंधों को केवल मैत्री और सहयोग की दृष्टि से नहीं, बल्कि शक्ति-संतुलन, छोटे राज्य की रणनीतिक स्वायत्तता, आर्थिक परस्पर निर्भरता तथा क्षेत्रीय सुरक्षा के

व्यापक परिप्रेक्ष्य में समझने का प्रयास करता है। इससे दक्षिण एशिया में भारत की पड़ोसी नीति तथा हिमालयी भू-राजनीति की प्रकृति को समझने में सहायता मिलती है।

अध्ययन के उद्देश्य

1. भारत-भूटान संबंधों के ऐतिहासिक एवं संधिगत विकास का विश्लेषण करना।
2. दोनों देशों के राजनीतिक, आर्थिक, ऊर्जा एवं सामरिक सहयोग की प्रकृति का मूल्यांकन करना।
3. चीन की क्षेत्रीय भूमिका और भारत-भूटान संबंधों पर उसके प्रभाव का परीक्षण करना।
4. द्विपक्षीय संबंधों की प्रमुख चुनौतियों की पहचान करते हुए सहयोग को अधिक संतुलित एवं टिकाऊ बनाने के उपाय प्रस्तुत करना।

शोध प्रश्न

1. भारत-भूटान संबंधों में संधिगत परिवर्तनों तथा राजनीतिक विश्वास की क्या भूमिका रही है?
2. चीन के साथ भूटान के सीमा-विवाद और भारत-चीन सामरिक प्रतिस्पर्धा ने द्विपक्षीय समीकरणों को किस प्रकार प्रभावित किया है?
3. आर्थिक परस्पर निर्भरता और भूटान की रणनीतिक स्वायत्तता के बीच संतुलन स्थापित करने की क्या संभावनाएँ हैं?

प्राक्कल्पनाएँ

1. भारत-भूटान संबंधों की स्थिरता का प्रमुख आधार ऐतिहासिक विश्वास, साझा सुरक्षा हित तथा संस्थागत सहयोग रहा है।
2. चीन की क्षेत्रीय सक्रियता और भूटान की विदेश नीति में विविधीकरण की आकांक्षा ने भारत-भूटान संबंधों को अधिक बहुआयामी बनाया है।
3. आर्थिक एवं ऊर्जा सहयोग को अधिक विविध, पारस्परिक रूप से लाभकारी और टिकाऊ बनाने से द्विपक्षीय संबंधों की दीर्घकालिक स्थिरता सुदृढ़ हो सकती है।

शोध-पद्धति

प्रस्तुत अध्ययन में गुणात्मक शोध-पद्धति का उपयोग किया गया है। अध्ययन का स्वरूप ऐतिहासिक, वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक रखा गया है। इसमें भारत और भूटान के बीच संपन्न संधियों, द्विपक्षीय संयुक्त वक्तव्यों, सरकारी प्रतिवेदनों, विदेश मंत्रालय के दस्तावेजों तथा प्रासंगिक पुस्तकों और शोध-साहित्य का अध्ययन किया गया। उपलब्ध तथ्यों का विषयवस्तु विश्लेषण करते हुए राजनीतिक विश्वास, सामरिक हित, आर्थिक निर्भरता और क्षेत्रीय शक्ति-संतुलन के परस्पर संबंधों का परीक्षण किया गया है। अध्ययन मुख्यतः द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है तथा इसमें किसी अप्रमाणित आँकड़े अथवा काल्पनिक सर्वेक्षण का उपयोग नहीं किया गया है।

साहित्य की समीक्षा

भारत-भूटान संबंधों के अध्ययन में ऐतिहासिक मैत्री, विदेश नीति, सामरिक सुरक्षा, आर्थिक परस्पर निर्भरता तथा हिमालयी भू-राजनीति से संबंधित साहित्य का विशेष महत्त्व है। इस विषय पर उपलब्ध पुस्तकों, शोध-अध्ययनों

और आधिकारिक दस्तावेजों की समीक्षा से स्पष्ट होता है कि भारत-भूटान संबंधों को केवल पारंपरिक मित्रता के आधार पर नहीं, बल्कि बदलते क्षेत्रीय शक्ति-संतुलन, भूटान की रणनीतिक स्वायत्तता और आर्थिक सहयोग की प्रकृति के संदर्भ में भी समझना आवश्यक है -

1. **ऐतिहासिक एवं राजनीतिक संबंधों पर साहित्य -** भारत-भूटान संबंधों के ऐतिहासिक और राजनीतिक स्वरूप को समझने के लिए वर्ष 1949 की मैत्री संधि तथा वर्ष 2007 में उसके संशोधित स्वरूप का अध्ययन महत्त्वपूर्ण है। इन संधियों से दोनों देशों के बीच विकसित संस्थागत संबंधों, सुरक्षा संबंधी परामर्श तथा पारस्परिक संप्रभुता के सम्मान में आए परिवर्तन का विश्लेषण किया जा सकता है। वर्ष 2007 की संधि ने विशेष रूप से भूटान की स्वतंत्र विदेश नीति और दोनों देशों की क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान को अधिक स्पष्ट आधार प्रदान किया। इस प्रकार संधिगत दस्तावेज भारत-भूटान संबंधों के ऐतिहासिक विकास को समझने के लिए प्राथमिक स्रोत के रूप में उपयोगी हैं।
2. रोजर चैपमैन (Roger Chapman) तथा अन्य विद्वानों के हिमालयी राजनीति से संबंधित अध्ययनों में क्षेत्रीय भूगोल, छोटे राज्यों की सुरक्षा तथा बाहरी शक्तियों के प्रभाव जैसे प्रश्न महत्त्वपूर्ण हैं। इस व्यापक साहित्य के आधार पर भूटान की भौगोलिक स्थिति को उसकी विदेश नीति और भारत के साथ संबंधों से जोड़कर समझा जा सकता है। हालांकि, किसी विशिष्ट लेखक के अध्ययन को भारत-भूटान संबंधों पर प्रत्यक्ष शोध तभी माना जाना चाहिए, जब उसमें इस द्विपक्षीय संबंध का स्पष्ट विश्लेषण उपलब्ध हो।
3. इस विषय में निताशा कौल (Kaul, 2022) का शोध-पत्र Beyond India and China: Bhutan as a Small State in International Relations विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यह शोध-पत्र International Relations of the Asia-Pacific में प्रकाशित हुआ। लेखिका ने भूटान की विदेश नीति को केवल भारत के साथ मैत्री और चीन से उत्पन्न सुरक्षा चुनौतियों के आधार पर समझने की प्रचलित प्रवृत्ति की आलोचनात्मक समीक्षा की है। उनके अध्ययन का प्रमुख तर्क है कि भूटान को केवल बड़ी शक्तियों के बीच स्थित एक छोटे राज्य के रूप में देखना पर्याप्त नहीं है; उसकी अपनी राजनीतिक परिस्थितियाँ, राष्ट्रीय प्राथमिकताएँ, कूटनीतिक पहल और ऐतिहासिक अनुभव भी विदेश नीति को प्रभावित करते हैं। डोकलाम प्रकरण के विश्लेषण के माध्यम से यह शोध भूटान की स्वतंत्र कूटनीतिक भूमिका को रेखांकित करता है। प्रस्तुत अध्ययन के लिए यह शोध विशेष रूप से उपयोगी है, क्योंकि यह भारत-भूटान संबंधों के विश्लेषण में भूटान की रणनीतिक स्वायत्तता को एक स्वतंत्र विश्लेषणात्मक आयाम प्रदान करता है।
4. इसी क्रम में ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन (ओआरएफ) द्वारा प्रकाशित The Changing Contours of Bhutan's Foreign Policy and the Implications for China and India (2022) भी प्रासंगिक अध्ययन है। इसमें भूटान की विदेश नीति में हो रहे परिवर्तनों और उनके भारत तथा चीन के साथ संबंधों पर पड़ने वाले प्रभावों का परीक्षण किया गया है। यह अध्ययन भूटान की भौगोलिक स्थिति, भारत के सुरक्षा हितों तथा चीन की बढ़ती क्षेत्रीय भूमिका के बीच अंतर्संबंध को समझने में सहायक है। इससे यह स्पष्ट होता है कि भारत-भूटान संबंधों का भविष्य केवल ऐतिहासिक निकटता पर निर्भर नहीं करता, बल्कि बदलते क्षेत्रीय सामरिक वातावरण और भूटान की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं से भी प्रभावित होता है।

5. **सामरिक सुरक्षा एवं डोकलाम विवाद पर साहित्य -** भारत-भूटान संबंधों के सामरिक पक्ष का अध्ययन करते समय डोकलाम गतिरोध और भारत-चीन प्रतिस्पर्धा से संबंधित शोध विशेष महत्त्व रखते हैं। इन अध्ययनों में डोकलाम की भौगोलिक स्थिति, चीन और भूटान के बीच सीमा विवाद तथा भारत की सुरक्षा संबंधी चिंताओं का विश्लेषण किया गया है। इस साहित्य से स्पष्ट होता है कि भूटान की क्षेत्रीय स्थिति उसके द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक हिमालयी सुरक्षा व्यवस्था से जोड़ती है। कौल (2022) का अध्ययन इस विमर्श में एक महत्त्वपूर्ण आलोचनात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। लेखिका के अनुसार, डोकलाम की घटनाओं को केवल भारत और चीन के बीच शक्ति-संघर्ष के रूप में प्रस्तुत करने से भूटान की अपनी कूटनीतिक भूमिका पर्याप्त रूप से सामने नहीं आती। इस दृष्टिकोण के आधार पर यह समझा जा सकता है कि भूटान केवल बाहरी शक्तियों की रणनीतियों से प्रभावित होने वाला निष्क्रिय पक्ष नहीं है, बल्कि वह अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सावधानीपूर्ण कूटनीति का प्रयोग भी करता है। अतः भारत-भूटान संबंधों के सामरिक विश्लेषण में भूटान की सुरक्षा संबंधी चिंताओं और स्वतंत्र निर्णय क्षमता दोनों को सम्मिलित करना आवश्यक है।
6. **आर्थिक परस्पर निर्भरता एवं जलविद्युत सहयोग पर साहित्य -** भारत-भूटान संबंधों के आर्थिक आयाम को समझने के लिए मनोरमा कोहली (Kohli, 1993) की पुस्तक From Dependency to Interdependence: A Study of Indo-Bhutan Relations उल्लेखनीय है। इस पुस्तक में दोनों देशों के ऐतिहासिक संबंधों, राजनीतिक विकास तथा आर्थिक परस्पर निर्भरता का अध्ययन किया गया है। पुस्तक का महत्त्व इस बात में है कि यह द्विपक्षीय संबंधों को केवल राजनीतिक मैत्री के रूप में नहीं, बल्कि आर्थिक और संस्थागत संबंधों के व्यापक संदर्भ में समझने का आधार प्रदान करती है। प्रस्तुत शोध में इस दृष्टिकोण का उपयोग भारत-भूटान आर्थिक संबंधों की प्रकृति तथा उनमें निहित पारस्परिक लाभ और निर्भरता का विश्लेषण करने के लिए किया गया है।

   जलविद्युत सहयोग के संबंध में सुप्पावित काउखुनोक (Kaewkhunok, 2019) का शोध-पत्र Hydroelectricity Generation and the Dynamics of India-Bhutan Relations विशेष रूप से प्रासंगिक है। इस अध्ययन में वर्ष 2007 की संशोधित मैत्री संधि के बाद भारत-भूटान संबंधों में जलविद्युत उत्पादन और निवेश की भूमिका का विश्लेषण किया गया है। लेखक के अनुसार, जलविद्युत सहयोग ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा में योगदान दिया है, जबकि भूटान की अर्थव्यवस्था और निवेश संबंधी आवश्यकताओं को भारत के साथ अधिक निकटता से जोड़ा है। यह अध्ययन ऊर्जा साझेदारी के दोहरे प्रभाव–आर्थिक विकास के अवसर तथा निर्भरता की संभावनाएँ–को समझने में उपयोगी है।

   इसी विषय पर सेसिलिया टोर्टाजादा और उदिशा सकलानी (Tortajada & Saklani, 2018) का शोध-पत्र Hydropower-based Collaboration in South Asia: The Case of India and Bhutan ऊर्जा नीति संबंधी साहित्य में महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। Energy Policy में प्रकाशित इस अध्ययन में भारत-भूटान जलविद्युत सहयोग, क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षा तथा सीमा-पार विद्युत व्यापार की संभावनाओं का परीक्षण किया गया है। अध्ययन यह रेखांकित करता है कि जलविद्युत सहयोग दोनों देशों के लिए लाभकारी होने के साथ दक्षिण एशिया में नवीकरणीय ऊर्जा के विकास की संभावनाएँ भी उत्पन्न करता है। इसके निष्कर्ष प्रस्तुत

शोध के आर्थिक विश्लेषण को आधार प्रदान करते हैं, विशेषकर इस प्रश्न पर कि ऊर्जा सहयोग को वित्तीय व्यवहार्यता और दीर्घकालिक स्थिरता के साथ किस प्रकार आगे बढ़ाया जा सकता है।

7. **भारत-भूटान संबंधों के बदलते समीकरणों पर साहित्य - जूही श्रीवास्तव** (Srivastava, 2021) की पुस्तक India-Bhutan Relations: Analysis of Changing Dynamics (from 2007-2017) में संशोधित मैत्री संधि के बाद के एक महत्त्वपूर्ण दशक में द्विपक्षीय संबंधों के बदलते स्वरूप का अध्ययन किया गया है। यह पुस्तक राजनीतिक एवं सामरिक परिवर्तनों के संदर्भ में भारत-भूटान संबंधों की निरंतरता और परिवर्तन को समझने के लिए उपयोगी है। विशेष रूप से, वर्ष 2007 के बाद विकसित संबंधों का अध्ययन वर्तमान शोध में संधिगत परिवर्तन और बदलती क्षेत्रीय परिस्थितियों के बीच संबंध स्थापित करने में सहायक है।

राजेश एस. खरात और **चुंकू भूटिया** (Kharat & Bhutia) का अध्याय Changing Dynamics of India-Bhutan Relations भी इस विषय से संबंधित अकादमिक साहित्य में उल्लेखनीय है। यह अध्याय स्मृति एस. पटनायक द्वारा संपादित पुस्तक India in South Asia: Challenges and Management में प्रकाशित हुआ है। इसमें भारत-भूटान संबंधों की बदलती प्रकृति का दक्षिण एशियाई राजनीति के व्यापक संदर्भ में अध्ययन किया गया है। इस प्रकार का विश्लेषण द्विपक्षीय संबंधों को भारत की पड़ोसी नीति तथा क्षेत्रीय राजनीतिक परिवर्तनों से जोड़कर समझने में सहायक है।

साहित्य का समग्र मूल्यांकन एवं शोध-अंतराल

उपर्युक्त साहित्य की समीक्षा से स्पष्ट होता है कि भारत-भूटान संबंधों के विभिन्न आयामों पर पर्याप्त उपयोगी अध्ययन उपलब्ध हैं। ऐतिहासिक एवं संधिगत अध्ययनों ने दोनों देशों के राजनीतिक संबंधों के विकास को स्पष्ट किया है; रणनीतिक अध्ययनों ने चीन की भूमिका, डोकलाम विवाद और हिमालयी सुरक्षा के महत्त्व को रेखांकित किया है; जबकि आर्थिक एवं ऊर्जा संबंधी शोधों ने जलविद्युत सहयोग, निवेश और परस्पर निर्भरता के प्रभावों का विश्लेषण किया है। इसके बावजूद, इन आयामों को अलग-अलग देखने के बजाय एक समेकित राजनीतिक दृष्टिकोण से समझने की आवश्यकता बनी हुई है। विशेष रूप से, भूटान की रणनीतिक स्वायत्तता, भारत की सुरक्षा संबंधी चिंताओं, चीन के साथ सीमा-वार्ता, आर्थिक निर्भरता तथा विकास सहयोग के बीच अंतर्संबंधों का संयुक्त मूल्यांकन इस विषय को अधिक व्यापक दृष्टि प्रदान कर सकता है। कौल (2022) का अध्ययन भूटान की स्वतंत्र कूटनीतिक भूमिका पर विशेष बल देता है, जबकि ऊर्जा संबंधी अध्ययनों से आर्थिक सहयोग के लाभों के साथ निर्भरता की सीमाएँ भी सामने आती हैं।

इसी आधार पर प्रस्तुत शोध-पत्र में भारत-भूटान संबंधों का आलोचनात्मक एवं एकीकृत विश्लेषण किया गया है। इसमें ऐतिहासिक मैत्री और संस्थागत सहयोग को आधार मानते हुए राजनीतिक, सामरिक तथा आर्थिक आयामों का परस्पर संबंधों के संदर्भ में परीक्षण किया गया है। अध्ययन का विशिष्ट योगदान यह है कि इसमें भारत के क्षेत्रीय सुरक्षा हितों के साथ भूटान की संप्रभुता, स्वतंत्र विदेश नीति और विकास संबंधी प्राथमिकताओं को भी समान महत्त्व दिया गया है। इस प्रकार शोध का उद्देश्य उपलब्ध साहित्य का पुनर्वर्णन करना मात्र नहीं, बल्कि बदलते दक्षिण एशियाई राजनीतिक परिवेश में द्विपक्षीय साझेदारी की उपलब्धियों, सीमाओं और भविष्य की संभावनाओं का समग्र मूल्यांकन करना है।

भारत-भूटान संबंधों का ऐतिहासिक एवं संधिगत विकास

भारत और भूटान के संबंध स्वतंत्रता के बाद क्रमशः अधिक संस्थागत एवं बहुआयामी होते गए। वर्ष 1949 की मैत्री संधि ने दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों और सुरक्षा संबंधी परामर्श की व्यवस्था को आधार प्रदान किया। इसके बाद वर्ष 1968 में राजनयिक संबंध स्थापित हुए, जिससे औपचारिक कूटनीतिक संपर्कों का विस्तार हुआ। वर्ष 2007 में मैत्री संधि का संशोधन द्विपक्षीय संबंधों के विकास में एक महत्त्वपूर्ण पड़ाव रहा। संशोधित संधि ने दोनों देशों की स्वतंत्रता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया। इस परिवर्तन ने भूटान की विदेश नीति संबंधी स्वायत्तता को अधिक स्पष्ट संस्थागत आधार प्रदान किया और भारत के साथ सहयोग को पारस्परिक विश्वास की दिशा में आगे बढ़ाया।

समय के साथ दोनों देशों के संबंध सुरक्षा और कूटनीति से आगे बढ़कर व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, अवसंरचना, डिजिटल प्रौद्योगिकी तथा ऊर्जा के क्षेत्रों तक विस्तृत हुए। भारत ने भूटान की विकास योजनाओं में महत्त्वपूर्ण वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान की है। दूसरी ओर, भूटान ने भारत के साथ स्थिर और सहयोगपूर्ण संबंधों को अपनी आर्थिक प्रगति तथा बाहरी सुरक्षा के लिए महत्त्वपूर्ण बनाए रखा है।इस ऐतिहासिक विकास से स्पष्ट होता है कि भारत-भूटान संबंधों की मजबूती केवल भौगोलिक निकटता का परिणाम नहीं है, बल्कि संधिगत निरंतरता, राजनीतिक विश्वास और दीर्घकालीन विकास सहयोग से भी निर्मित हुई है।

भारत-भूटान संबंधों के प्रमुख आयाम

1. **राजनीतिक एवं कूटनीतिक सहयोग -** भारत और भूटान के बीच नियमित उच्चस्तरीय यात्राएँ, संयुक्त वक्तव्य तथा विभिन्न संस्थागत संवाद राजनीतिक विश्वास को बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मार्च 2024 में भारतीय प्रधानमंत्री की भूटान यात्रा के दौरान ऊर्जा साझेदारी, डिजिटल संपर्क, अंतरिक्ष सहयोग तथा विकास संबंधी विषयों पर समझौते हुए। इन पहलों से स्पष्ट होता है कि संबंध पारंपरिक कूटनीति से आगे बढ़कर नई विकास आवश्यकताओं के अनुरूप विस्तृत हुए हैं। राजनीतिक सहयोग का महत्त्व इस तथ्य में भी निहित है कि दोनों देशों के बीच विवादों को संवाद और संस्थागत तंत्र के माध्यम से संबोधित करने की परंपरा रही है। फिर भी, इस साझेदारी का दीर्घकालिक आधार तभी मजबूत रह सकता है, जब भारत भूटान की स्वतंत्र प्राथमिकताओं और निर्णय लेने की क्षमता के प्रति संवेदनशील बना रहे।
2. **सामरिक एवं सुरक्षा सहयोग -** भूटान की भौगोलिक स्थिति उसे हिमालयी सुरक्षा व्यवस्था का महत्त्वपूर्ण अंग बनाती है। भारत के सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल के निकट स्थित भूटानी क्षेत्र का सामरिक महत्त्व विशेष रूप से उल्लेखनीय है। भारत-चीन सीमा के निकटवर्ती क्षेत्र में स्थिरता दोनों देशों के सुरक्षा हितों से जुड़ी हुई है। वर्ष 2017 का डोकलाम गतिरोध इस परस्पर संबंध का उल्लेखनीय उदाहरण है। डोकलाम भूटान और चीन के बीच विवादित क्षेत्र है, जो भारत के लिए भी सामरिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। इस घटनाक्रम ने स्पष्ट किया कि भूटान के सीमा-संबंधी प्रश्न व्यापक क्षेत्रीय शक्ति-संतुलन को प्रभावित कर सकते हैं। भारत के लिए आवश्यक है कि वह भूटान के साथ सुरक्षा समन्वय बनाए रखते हुए उसके संप्रभु निर्णयों और कूटनीतिक प्रक्रियाओं का सम्मान करे। सुरक्षा सहयोग का व्यापक अर्थ केवल

सैन्य हितों की रक्षा नहीं है। इसमें सीमा प्रबंधन, अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण, सूचना-साझाकरण तथा क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने के प्रयास भी सम्मिलित हैं। अतः भारत-भूटान सामरिक साझेदारी को साझा हितों और परस्पर विश्वास के आधार पर समझना अधिक उपयुक्त है।

3. **चीन-भूटान सीमा विवाद एवं क्षेत्रीय शक्ति-संतुलन -** चीन और भूटान के बीच सीमा का औपचारिक परिसीमन अब तक नहीं हुआ है। दोनों देशों के बीच 1984 से सीमा वार्ताएँ होती रही हैं तथा वर्ष 2021 में सीमा-वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए तीन-चरणीय रूपरेखा पर सहमति बनी। भूटान और चीन के बीच औपचारिक राजनयिक संबंध स्थापित न होने के बावजूद सीमा प्रश्न पर संवाद जारी रहा है। भारत के दृष्टिकोण से इस विवाद का महत्त्व डोकलाम तथा भारत-चीन सीमा के निकटवर्ती क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति के कारण बढ़ जाता है। यदि चीन और भूटान के बीच सीमा समझौता होता है, तो उसका प्रभाव क्षेत्रीय सुरक्षा, संपर्क मार्गों और भारत की सामरिक गणनाओं पर पड़ सकता है। हालांकि, किसी संभावित समझौते के परिणामों का आकलन उसके वास्तविक प्रावधानों और भौगोलिक स्वरूप के आधार पर ही किया जाना चाहिए। दूसरी ओर, भूटान के लिए चीन के साथ सीमा विवाद का समाधान अपनी क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्र विदेश नीति से जुड़ा विषय है। इसलिए भूटान की कूटनीतिक पहल को केवल भारत-चीन प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में देखना उसकी स्वतंत्र राजनीतिक भूमिका को सीमित कर देगा। भारत के लिए अधिक प्रभावी नीति वह होगी, जो सुरक्षा हितों के साथ भूटान की संप्रभुता और दीर्घकालीन विश्वास को समान महत्त्व दे।

4. **आर्थिक एवं व्यापारिक परस्पर निर्भरता -** भारत भूटान का प्रमुख व्यापारिक साझेदार तथा विकास सहयोग का महत्त्वपूर्ण स्रोत रहा है। वर्ष 2024 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग ₹12,669 करोड़ रहा। इसमें भारत का भूटान को निर्यात लगभग ₹9,538 करोड़ और भूटान से आयात लगभग ₹3,131 करोड़ था। इसी अवधि में भूटान के कुल व्यापार में भारत की हिस्सेदारी लगभग 79.88 प्रतिशत रही। ये आँकड़े दोनों अर्थव्यवस्थाओं के बीच गहरी परस्पर निर्भरता को दर्शाते हैं। यह निर्भरता भूटान को बड़े बाजार, आवश्यक वस्तुओं तथा निवेश तक पहुँच प्रदान करती है। भारत को भी भूटान से जलविद्युत और अन्य वस्तुओं की आपूर्ति के माध्यम से आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। किंतु व्यापारिक संबंधों में अत्यधिक एकाग्रता भूटान के लिए बाजार विविधीकरण की आवश्यकता उत्पन्न करती है। इसलिए आर्थिक सहयोग की गुणवत्ता का मूल्यांकन केवल व्यापार की मात्रा से नहीं, बल्कि स्थानीय उत्पादन, रोजगार, निर्यात विविधीकरण और दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता के आधार पर भी किया जाना चाहिए।

5. **जलविद्युत एवं ऊर्जा सहयोग -** जलविद्युत भारत-भूटान आर्थिक साझेदारी का केंद्रीय आधार रहा है। चुखा, कुरिच्छू, ताला और मंगदेछू जैसी परियोजनाओं ने भूटान की विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने और भारत को बिजली उपलब्ध कराने में योगदान दिया। दोनों देशों ने पुनात्सांगछू-I परियोजना के मुख्य बाँध पर कार्य पुनः आरंभ करने की सहमति का भी स्वागत किया। ऊर्जा सहयोग से भूटान को निर्यात आय तथा विकास के लिए संसाधन प्राप्त होते हैं, जबकि भारत को स्वच्छ ऊर्जा की उपलब्धता बढ़ाने में सहायता मिलती है। इसके बावजूद बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं की लागत, निर्माण में विलंब, ऋण एवं वित्तीय जोखिम, पर्यावरणीय प्रभाव तथा मौसमी विद्युत उपलब्धता जैसे प्रश्न महत्त्वपूर्ण बने हुए हैं।

अतः भविष्य की ऊर्जा साझेदारी को केवल बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं तक सीमित न रखकर सौर ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, ऊर्जा भंडारण और विद्युत व्यापार के विविध माध्यमों तक विस्तारित करना आवश्यक है। इससे दोनों देशों की ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक साझेदारी अधिक टिकाऊ बन सकती है।

6. **संपर्क, अवसंरचना एवं विकास सहयोग -** भारत-भूटान संबंधों में सड़क, व्यापार मार्ग, डिजिटल नेटवर्क और सीमा-पार परिवहन का महत्त्व लगातार बढ़ा है। इसमें कोकराझार-गेलेफू तथा बनारहाट-समत्से रेल संपर्कों की योजना शामिल थी, जिनकी प्रस्तावित कुल लंबाई लगभग 89 किलोमीटर और अनुमानित लागत ₹4,033.34 करोड़ निर्धारित की गई। ऐसे संपर्क मार्ग व्यापार, पर्यटन, निवेश और लोगों के बीच आदान-प्रदान को प्रोत्साहित कर सकते हैं। भूटान की विकास आवश्यकताओं के संदर्भ में भारत की सहायता का महत्त्व स्पष्ट है, लेकिन परियोजनाओं की सफलता के लिए स्थानीय पर्यावरण, समुदायों के हितों और आर्थिक व्यवहार्यता को भी प्राथमिकता देना आवश्यक है।

भारत द्वारा भूटान की तेरहवीं पंचवर्षीय योजना (2024-2029) के लिए विकास सहायता बढ़ाना भी द्विपक्षीय संबंधों के विकासपरक पक्ष को रेखांकित करता है। इस सहयोग का वास्तविक मूल्यांकन तभी संभव है, जब परियोजनाओं से उत्पादक क्षमता, रोजगार, कौशल विकास तथा सामाजिक कल्याण में मापनीय सुधार उत्पन्न हों।

सैद्धांतिक आधार एवं आलोचनात्मक विश्लेषण

भारत-भूटान संबंधों को समझने के लिए यथार्थवाद, उदार संस्थावाद तथा छोटे राज्य की रणनीतिक स्वायत्तता की अवधारणाएँ उपयोगी हैं। यथार्थवाद एवं शक्ति-संतुलन: यथार्थवादी दृष्टिकोण के अनुसार राज्य अपनी सुरक्षा, क्षेत्रीय हितों और शक्ति-संतुलन को प्राथमिकता देते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में भूटान की भौगोलिक स्थिति, चीन के साथ सीमा विवाद तथा भारत की हिमालयी सुरक्षा संबंधी चिंताएँ द्विपक्षीय साझेदारी के सामरिक महत्त्व को स्पष्ट करती हैं। डोकलाम प्रकरण इस बात का उदाहरण है कि सीमावर्ती विवाद व्यापक क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा से जुड़ सकते हैं। उदार संस्थावाद एवं परस्पर निर्भरता: उदार संस्थावादी दृष्टिकोण संधियों, संवाद, व्यापार और संस्थागत सहयोग को स्थिर संबंधों का आधार मानता है। वर्ष 2007 की मैत्री संधि, विकास सहयोग वार्ताएँ और ऊर्जा परियोजनाएँ इस दृष्टिकोण की उपयोगिता को प्रदर्शित करती हैं। नियमित संवाद से विवादों के शांतिपूर्ण समाधान और सहयोग के विस्तार की संभावनाएँ बढ़ती हैं। छोटे राज्य की रणनीतिक स्वायत्तता: भूटान की विदेश नीति का विश्लेषण केवल भारत-चीन प्रतिस्पर्धा के आधार पर नहीं किया जा सकता। भूटान अपनी सुरक्षा आवश्यकताओं के साथ आर्थिक विकास, अंतरराष्ट्रीय संपर्क और स्वतंत्र निर्णय क्षमता को भी महत्त्व देता है। इसलिए उसकी विदेश नीति में विविधीकरण की आकांक्षा को भारत के प्रति विरोध के रूप में देखना उचित नहीं होगा।

आलोचनात्मक रूप से देखा जाए तो भारत-भूटान संबंधों में सहयोग और असमानता दोनों के तत्त्व मौजूद हैं। भारत की आर्थिक एवं सामरिक क्षमता अधिक है, जबकि भूटान की भौगोलिक स्थिति उसे विशिष्ट रणनीतिक महत्त्व प्रदान करती है। इस असमानता को संतुलित करने के लिए भारत को सहयोगी की भूमिका में पारस्परिक सम्मान, पारदर्शिता और भूटान की विकास प्राथमिकताओं को केंद्र में रखना होगा।

प्रमुख चुनौतियाँ

भारत-भूटान संबंधों के समक्ष निम्नलिखित चुनौतियाँ विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं :

1. चीन के साथ सीमा विवाद: सीमा परिसीमन और डोकलाम जैसे संवेदनशील क्षेत्रों से जुड़े प्रश्न क्षेत्रीय सुरक्षा की अनिश्चितता बनाए रखते हैं।
2. आर्थिक निर्भरता: भारत के साथ व्यापार की अत्यधिक एकाग्रता भूटान के लिए बाजारों और निवेश स्रोतों में विविधता बढ़ाने की आवश्यकता को रेखांकित करती है।
3. जलविद्युत परियोजनाओं की व्यवहार्यता: निर्माण में विलंब, वित्तीय जोखिम, पर्यावरणीय प्रभाव और परियोजना लागत ऊर्जा सहयोग के लाभों को प्रभावित कर सकते हैं।
4. भूटान की रणनीतिक स्वायत्तता: भारत के सुरक्षा हितों तथा भूटान की स्वतंत्र कूटनीतिक प्राथमिकताओं के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है।
5. बदलती क्षेत्रीय भू-राजनीति: भारत-चीन संबंधों में प्रतिस्पर्धा और संवाद दोनों की स्थिति भूटान की विदेश नीति तथा भारत की क्षेत्रीय रणनीति को प्रभावित करती है।

इन चुनौतियों से स्पष्ट है कि ऐतिहासिक मैत्री संबंधों की मजबूती के लिए पर्याप्त आधार अवश्य है, लेकिन बदलती परिस्थितियों में सहयोग को निरंतर अनुकूलित करना भी आवश्यक है।

निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन के विश्लेषण से निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं।

- भारत-भूटान संबंधों का प्रमुख आधार ऐतिहासिक विश्वास, संधिगत निरंतरता और साझा विकास संबंधी हित रहे हैं।
- वर्ष 2007 की संशोधित मैत्री संधि ने द्विपक्षीय संबंधों में संप्रभु समानता और भूटान की स्वतंत्र विदेश नीति के महत्त्व को अधिक स्पष्ट किया।
- चीन के साथ भूटान का सीमा विवाद भारत के सामरिक हितों से जुड़ा है, किंतु भूटान की कूटनीतिक भूमिका को स्वतंत्र रूप से समझना भी आवश्यक है।
- व्यापार और जलविद्युत सहयोग दोनों देशों के लिए लाभकारी हैं, लेकिन आर्थिक निर्भरता तथा परियोजना संबंधी जोखिमों के कारण सहयोग के विविधीकरण की आवश्यकता बनी हुई है।
- संपर्क अवसंरचना, डिजिटल प्रौद्योगिकी और नवीकरणीय ऊर्जा में सहयोग भारत-भूटान संबंधों को पारंपरिक सुरक्षा साझेदारी से आगे ले जाने की क्षमता रखते हैं।
- द्विपक्षीय संबंधों की दीर्घकालिक स्थिरता केवल साझा सुरक्षा हितों पर नहीं, बल्कि पारस्परिक सम्मान, आर्थिक लाभों के संतुलित वितरण और भूटान की निर्णय-स्वायत्तता के प्रति संवेदनशीलता पर भी निर्भर करती है।

समग्र रूप से, अध्ययन की पहली प्राक्कल्पना को ऐतिहासिक एवं संस्थागत साक्ष्यों से पर्याप्त समर्थन प्राप्त हुआ। दूसरी प्राक्कल्पना भी क्षेत्रीय शक्ति-संतुलन तथा भूटान की विकास संबंधी प्राथमिकताओं के विश्लेषण से समर्थित होती है। तीसरी प्राक्कल्पना के संदर्भ में आर्थिक विविधीकरण और टिकाऊ ऊर्जा सहयोग की संभावनाएँ स्पष्ट हुईं, यद्यपि उनके दीर्घकालिक परिणामों का आकलन वास्तविक क्रियान्वयन के आधार पर ही किया जा सकता है। भारत-भूटान संबंध समकालीन दक्षिण एशियाई राजनीति में विश्वास, सहयोग और साझा हितों पर आधारित द्विपक्षीय साझेदारी का महत्त्वपूर्ण उदाहरण हैं। इन संबंधों की विशेषता यह है कि ऐतिहासिक निकटता के साथ-साथ

दोनों देशों ने बदलती राजनीतिक एवं आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप सहयोग के नए क्षेत्र विकसित किए हैं। संशोधित मैत्री संधि, विकास सहायता, जलविद्युत परियोजनाएँ और संपर्क अवसंरचना इस साझेदारी के प्रमुख आधार हैं। इसके बावजूद चीन के साथ भूटान का सीमा विवाद, भारत-चीन प्रतिस्पर्धा, आर्थिक निर्भरता तथा भूटान की रणनीतिक स्वायत्तता से जुड़े प्रश्न संबंधों के समक्ष जटिल चुनौतियाँ प्रस्तुत करते हैं। इन चुनौतियों का समाधान किसी एक देश की प्राथमिकताओं को दूसरे पर थोपने में नहीं, बल्कि संवाद, विश्वास और पारस्परिक लाभ के आधार पर सहयोग को विकसित करने में निहित है।

अतः निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि भारत-भूटान संबंधों का भविष्य पारंपरिक मित्रता को बनाए रखने के साथ-साथ उसे अधिक संतुलित, विविधतापूर्ण और टिकाऊ साझेदारी में रूपांतरित करने पर निर्भर करेगा। यदि दोनों देश सुरक्षा सहयोग के साथ आर्थिक अवसरों का विस्तार करें और भूटान की संप्रभुता तथा स्वतंत्र निर्णय क्षमता का सम्मान बनाए रखें, तो यह साझेदारी न केवल द्विपक्षीय हितों को सुदृढ़ करेगी, बल्कि दक्षिण एशिया में शांति, स्थिरता और क्षेत्रीय सहयोग को भी सकारात्मक दिशा प्रदान कर सकती है।

सुझाव

1. रणनीतिक संवाद को सुदृढ़ करना: भारत और भूटान को सीमा सुरक्षा, क्षेत्रीय घटनाक्रम तथा सामरिक चिंताओं पर नियमित और पारदर्शी संवाद बनाए रखना चाहिए।
2. भूटान की संप्रभुता का सम्मान: भारत की नीतियों में भूटान की स्वतंत्र विदेश नीति, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और कूटनीतिक निर्णयों के प्रति संवेदनशीलता सुनिश्चित की जानी चाहिए।
3. आर्थिक विविधीकरण को प्रोत्साहन: जलविद्युत के अतिरिक्त पर्यटन, कृषि-प्रसंस्करण, सूचना प्रौद्योगिकी, कौशल विकास और लघु उद्योगों में सहयोग बढ़ाया जाना चाहिए।
4. ऊर्जा सहयोग को टिकाऊ बनाना: जलविद्युत परियोजनाओं के साथ सौर ऊर्जा, ऊर्जा भंडारण तथा पर्यावरणीय आकलन पर ध्यान देना चाहिए। परियोजनाओं की वित्तीय व्यवहार्यता और लाभों का पारदर्शी मूल्यांकन भी आवश्यक है।
5. क्षेत्रीय संपर्क का संतुलित विस्तार: रेल, सड़क और डिजिटल संपर्क परियोजनाओं को स्थानीय आवश्यकताओं, पर्यावरण संरक्षण तथा आर्थिक उपयोगिता के अनुरूप आगे बढ़ाया जाना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. भारत सरकार, विदेश मंत्रालय, (2007, 8 फरवरी), भारत गणराज्य की सरकार और भूटान की शाही सरकार के बीच मैत्री संधि, भारत सरकार, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार।
2. भारत सरकार, विदेश मंत्रालय, (2024), भारत-भूटान संबंध: द्विपक्षीय संबंधों पर आधिकारिक विवरण, भारत सरकार, भारत-भूटान संबंध संबंधी प्रतिवेदन।
3. भूटान की शाही सरकार, विदेश मंत्रालय एवं विदेश व्यापार मंत्रालय, (2024, 30 जून), भूटान-भारत विकास सहयोग वार्ता पर संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति, आधिकारिक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति।
4. भारत सरकार, प्रधानमंत्री कार्यालय, (2024, 11 नवंबर), भारत के प्रधानमंत्री की भूटान यात्रा पर संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति, प्रधानमंत्री कार्यालय का आधिकारिक दस्तावेज।

5. कौल, निताशा, (2022), Beyond India and China: Bhutan as a small state in international relations, Internationa, Relations of the Asia-Pacific, 22(2), p. 297.
6. कोहली, मनोरमा, (1993), From dependency to interdependence: A study of Indo-Bhutan relations, विकास पब्लिशिंग हाउस।
7. काउखुनोक, सुप्पावित, (2019), Hydroelectricity generation and the dynamics of India-Bhutan relations, शोध-पत्र।
8. टोर्टाजादा, सेसिलिया, एवं सकलानी, उदिशा, (2018)। Hydropower-based collaboration in South Asia: The case of India and Bhutan। Energy Policy, 116, p. 316.
9. श्रीवास्तव, जूही, (2021), India-Bhutan relations: Analysis of changing dynamics (from 2007-2017), पैसिफिक बुक्स इंटरनेशनल।
10. खरात, राजेश एस., एवं भूटिया, चुंकू, (2019), Changing dynamics of India-Bhutan relations। में: स्मृति एस. पटनायक (संपा.), India in South Asia: Challenges and Management। स्प्रिंगर।
11. भारतीय दूतावास, थिम्पू, (2024), भूटान के साथ भारत के संबंध: विदेश मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 के अंश,भारत सरकार, आधिकारिक प्रतिवेदन।
12. भूटान की शाही सरकार, नई दिल्ली स्थित भूटानी दूतावास, भूटान-भारत जलविद्युत संबंध, आधिकारिक ऊर्जा सहयोग विवरण।
13. भारत सरकार, विदेश मंत्रालय, भारत-भूटान द्विपक्षीय संबंध, भारत सरकार, भारत-भूटान संबंधों का आधिकारिक विवरण।
14. चीन जनवादी गणराज्य, विदेश मंत्रालय, चीन और भूटान: द्विपक्षीय संबंध एवं सीमा प्रश्न, चीन के विदेश मंत्रालय का आधिकारिक विवरण।
15. मॉर्गेन्थाऊ, हान्स जे. (1948), राष्ट्रों के बीच राजनीति: शक्ति और शांति के लिए संघर्ष, अल्फ्रेड ए. नॉफ।
16. कीओहेन, रॉबर्ट ओ. (1984), वर्चस्व के बाद: विश्व राजनीतिक अर्थव्यवस्था में सहयोग और कलह, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस।

ISARA INSTITUTE OF MANAGEMENT & PROFESSIONAL STUDIES

WWW.IIMPS.IN

EARN YOUR

MBA



Accreditation & Ranking

UGC / NCTE Approved.

INFO@IIMPS.IN

011-41005174

RESEARCH GATEWAY

STOP PLAGIARISM

1 Submit your content in Word File.

2 Get report in 48 hrs.

3 *Missing content or references will be fixed.

4 Citation for your work.

5 Get accurate user friendly report.

researchgateway.in | info@researchgateway.in

+91-9205579779

AROGYAM ONLINE

Arogyam Ayurveda

Holistic Healing through herbs

100% NATURAL

PARIVARTAN PSYCHOLOGY CENTER

COLOR PSYCHOLOGY : HOW COLOR AFFECT YOUR CHILD

BLUE — Calms your Child's Mind & Body

YELLOW — Promotes Concentration, Stimulates the Memory

PINK — Evokes Empathy, makes your Child Calm

RED — Excites and energizes your Child's body

GREEN — Improves Reading speed and Comprehension

www.parivartan4u.com

Confuse about your children's future?

भारतीय भाषा, शिक्षा, साहित्य एवं शोध

ISSN 2321 – 9726

WWW.BHARTIYASHODH.COM

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF MANAGEMENT SCIENCE & TECHNOLOGY

ISSN – 2250 – 1959 (0) 2348 – 9367 (P)

WWW.IRJMST.COM

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF COMMERCE, ARTS AND SCIENCE

ISSN 2319 – 9202

WWW.CASIRJ.COM

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF MANAGEMENT SOCIOLOGY & HUMANITIES

ISSN 2277 – 9809 (0) 2348 - 9359 (P)

WWW.IRJMSH.COM

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF SCIENCE ENGINEERING AND TECHNOLOGY

ISSN 2454-3195 (online)

WWW.RJSET.COM

INTEGRATED RESEARCH JOURNAL OF MANAGEMENT, SCIENCE AND INNOVATION

ISSN 2582-5445

WWW.IRJMSI.COM

JOURNAL OF LEGAL STUDIES,POLITICS AND ECONOMICS RESEARCH

WWW.JLPER.COM